

[2020] 1 एस. सी. आर. 523

चंदेश्वर साव

बनाम

बृज भूषण प्रसाद और अन्य

(2020 की दीवानी अपील सं.780)

28 जनवरी, 2020

[ए.एम. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्तिगण]

चुनाव कानून:

पंचायत चुनाव-निर्वाचन याचिकाकर्ता द्वारा लौटे उम्मीदवार के खिलाफ शिकायत-यह आरोप लगाते हुए कि आपत्ति के बावजूद, उनके पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या को अस्वीकार किया जा रहा था और लौटे उम्मीदवार के पक्ष में अमान्य मतों को स्वीकार कर लिया गया था-न्यायाधिकरण ने मतों की गिनती में अनियमितताओं को देखते हुए उनके चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया और मतों की फिर से गिनती का निर्देश दिया-रिट याचिका में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने कहा कि मतों की फिर से गिनती से पहले, लौटे उम्मीदवार के चुनाव को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए था और पुनर्मतगणना के परिणाम के बाद उचित आदेश पारित करने के लिए दलों को न्यायाधिकरण में भेज दिया जाना चाहिए था-पुनर्मतगणना प्रक्रिया के बाद, परिणामों को सीलबंद लिफाफे में रखा गया था-एकल के आदेश के खिलाफ एल.पी.ए. दायर किया गया न्यायाधीश-परिणाम की घोषणा के लिए जिला चुनाव अधिकारी-सह-जिला दंडाधिकारी के समक्ष परिणाम को सीलबंद लिफाफे में रखने का न्यायाधिकरण का निर्देश-जिसे रिट याचिका के माध्यम से लौटे उम्मीदवार द्वारा चुनौती दी गई थी-एल. पी. ए. के साथ-साथ लौटे उम्मीदवार की रिट याचिका का फैसला चुनाव याचिकाकर्ता के खिलाफ किया गया था,

जिसमें मतों की फिर से गिनती के निर्देश को दरकिनार कर दिया गया था-सर्वोच्च न्यायालय में अपील-आयोजित: खंड पीठ ने दलीलों और सबूतों का विश्लेषण किए बिना चुनाव न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के सुविचारित फैसले को उलट दिया। धारा 140 बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के तहत यह जारी किया गया है कि लौटने वाले उम्मीदवार का चुनाव अमान्य है और चुनाव याचिकाकर्ता को विधिवत निर्वाचित घोषित किया गया है-बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 -एस. 140.

अपील का निपटारा करते हुए,

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया : 1.1 उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने चुनाव न्यायाधिकरण के सुविचारित निर्णय को उलट दिया, जिसे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों और साक्ष्य का विश्लेषण किए बिना उचित रूप से बरकरार रखा है। चुनाव मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव याचिकाकर्ता विवादित निर्णय केवल उत्तरदाताओं संख्या 1 और एल.पी.ए. द्वारा दायर रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान पारित अंतरिम आदेशों का विज्ञापन करता है और यह अवलोकन करता है कि उसमें दर्ज (प्रथम दृष्टया) राय के लिए, मुद्दे में मामला अपीलार्थी/चुनाव याचिकाकर्ता के खिलाफ और उत्तरदाताओं संख्या 1 के पक्ष में जवाब देने का हकदार है। [कंडिका 8] [533-ए-सी]

1.2 निर्वाचन न्यायाधिकरण द्वारा इस प्रकार अभिलिखित तथ्यों के निष्कर्ष को उलट दिए बिना, केवल इस न्यायालय के निर्णयों को संदर्भित करके, खंड पीठ वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों में निर्वाचन न्यायाधिकरण द्वारा निर्देशित पुनर्मतगणना के आदेश को बाधित नहीं कर सकती थी। चूंकि, अपीलार्थी/चुनाव याचिकाकर्ता ने न केवल उत्तरदाताओं संख्या 1 के पक्ष में डाले गए वैध मतों और अमान्य मतों की गिनती के

दौरान अधिकारियों द्वारा की गई गंभीर अनियमितताओं के बारे में अनुरोध किया था, बल्कि उस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए गवाहों से भी पूछताछ की थी, जैसा कि चुनाव न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने उल्लेख किया है।
[कंडिका 8] [536-एफ-एच]

महेन्द्र प्रताप बनाम कृष्ण पाल और अन्य (2003) 1 एससीसी 390 :[2002]

4 पूरक एससीआर 339- प्रतिष्ठित।

भाभी बनाम शीओ गोविंद और अन्य। (1976) 1 एससीसी 687; [1975]

पूरक। एस. सी. आर. 202-संदर्भित।

1.3 चूँकि अपीलार्थी ने चुनाव याचिका में लगाए गए आरोप की पुष्टि की थी और निर्वाचन न्यायाधिकरण ने उक्त दावे के बारे में आश्वस्त होने के बाद फिर से गिनती का आदेश जारी किया। चुनाव न्यायाधिकरण के उस दृष्टिकोण में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है और न ही यह सुझाव देना संभव है कि चुनाव न्यायाधिकरण या एकल न्यायाधीश गिनती के दौरान अधिकारियों द्वारा की गई गंभीर अनियमितताओं के बारे में आरोप को साबित करने की आवश्यकता के बारे में सचेत नहीं थे। न्यायालय या न्यायाधिकरण मतों की फिर से गिनती का निर्देश दे सकता है, भले ही पार्टी ने निर्वाचन अधिकारी को मतों की फिर से गिनती के लिए लिखित रूप में आवेदन नहीं किया हो। बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 या नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो न्यायालय या न्यायाधिकरण को मतों की पुनः गिनती का निर्देश देने से रोकता हो।
[कंडिका 9 और 10] [538-ए-बी, ई]

सोहन लाल बनाम बाबू गांधी और अन्य। (2003) 1 एससीसी 108: [2002]

4 पूरक। एस. सी. आर. 333-पर निर्भर।

राम रति (श्रीमती) बनाम सरोज देवी और अन्य। (1997) 6 एससीसी 66:

[1997] 3 एस. सी. आर. 1050-खारिज कर दिया गया।

1.4 पुनः गणना के बाद, अपीलार्थी/चुनाव याचिकाकर्ता ने 95 अतिरिक्त वैध मत प्राप्त किए हैं, जो उत्तरदाताओं संख्या 1 द्वारा प्राप्त वैध मतों से अधिक हैं। इसने अपीलार्थी द्वारा स्थापित चुनौती को और मजबूत किया है कि अधिकारियों ने अपीलार्थी द्वारा प्राप्त वैध मतों में जानबूझकर हेरफेर करने के लिए गंभीर अनियमितताएं की थीं। नतीजतन, न्यायालय ने वर्तमान मामले के तथ्यों में, निर्वाचन न्यायाधिकरण (दिनांक 11.10.2018) द्वारा पारित और एकल न्यायाधीश द्वारा न्यायसंगत रूप से बरकरार रखे गए मतों की फिर से गिनती के आदेश को बरकरार रखा।[कंडिका 11] [539-सी-डी]

2. चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा परिणाम की घोषणा के लिए सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट को जिला चुनाव अधिकारी-सह-जिला दंडाधिकारी के समक्ष रखने का निर्देश, भले ही अनुचित हो, मतों की फिर से गिनती के आदेश को प्रभावित नहीं करेगा। यह उच्च न्यायालय के लिए खुला था कि वह चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा जारी निर्देश को ढाले और इसके बजाय बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 140 के तहत घोषणा जारी करे। अधिनियम की धारा 140 के तहत एक घोषणा जारी की जाती है कि उत्तरदाताओं संख्या 1 का वापस लौटे उम्मीदवार के रूप में चुनाव अमान्य होने के कारण रद्द कर दिया जाता है, और इसके बजाय अपीलार्थी/चुनाव याचिकाकर्ता को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में सबसे अधिक वोट और विषय चुनाव में उत्तरदाताओं संख्या 1 की तुलना में 95 अधिक वैध वोट प्राप्त करके विधिवत निर्वाचित घोषित किया जाता है।[पारस 12 और 14] [539-ई-एफ; 541-ए-बी]

3.1. निर्वाचन न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश, दिनांक 11.4.2019, जो उत्तरदाताओं संख्या 1 द्वारा दायर रिट याचिका का विषय था, ने भी न्यायाधिकरण के

अभिलेख/दस्तावेजों की जालसाजी का आरोप लगाते हुए उसके समक्ष दायर आवेदन पर विचार किया। न्यायाधिकरण ने ठीक ही कहा है कि यह एक अलग मामला है और इसके लिए स्वतंत्र जांच की आवश्यकता होगी, जिसके लिए याचिका को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत एक याचिका के रूप में माना गया है, जिससे कानून के अनुसार निपटा जा सके।[कंडिका 13] [540-डी-ई]

3.2. उत्तरदाता संख्या 1 ने निर्णय के लिए मामला सुरक्षित रखे जाने के बाद दायर लिखित प्रस्तुतियों के माध्यम से कुछ तथ्यात्मक मामलों की ओर रुख किया है, ताकि मर्तों की पुनः गिनती के परिणाम पर सवाल उठाया जा सके। संभवतः, कमीशन या चूक के कथित कार्य पहले से ही दं.प्र.सं. की धारा 340 के तहत शुरू की गई कार्यवाही के विषय हैं। इसके लिए न्यायालय को इस मामले का निपटारा करने से रोकने की आवश्यकता नहीं है। विवादित फैसले में नए तथ्यात्मक मामलों का उल्लेख नहीं मिलता है। उत्तरदाता संख्या 1 के लिए यह खुला रहेगा कि वह दं.प्र.सं. की धारा 340 के तहत कार्यवाही को आगे बढ़ा सके, जिसका निर्णय कानून के अनुसार अपने गुण-दोष के आधार पर करना होगा। [कंडिका 13] [540-एफ-एच]

नजीर संदर्भ

[2002] 4 पूरक एस.सी.आर. 339	विशिष्ट	कंडिका 5
[1975] पूरक एस.सी.आर. 202	संदर्भित करता है	कंडिका 5
[2002] 4 पूरक एस.सी.आर. 333	पर निर्भर	कंडिका 10
[1997] 3 एस. सी. आर. 1050	खारिज कर दिया गया	कंडिका 10

2019 के लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 382 में पटना में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 27.08.2019 से।

अमित पवन, अभिषेक अमृतांशु, आनंद नंदन, अक्षत श्रीवास्तव, हसन जुबैर वारिस, रोहित राजेशी, सुश्री शिवांगी, अपीलार्थी के लिए अधिवक्तागण

अभय कुमार, विनीत कुमार सिंह, कुमार मिलिंद, गोपाल सिंह, मनीष कुमार, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्तागण

न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर द्वारा दिया गया था

1. अनुमति दी जाती है।

2. यह अपील पटना उच्च न्यायालय (संक्षेप में, 'उच्च न्यायालय') द्वारा पारित दिनांक 27.8.2019 के निर्णय और आदेश पर आपत्ति उठाती है, जिससे विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश, दिनांक 6.3.2019 और दीवानीन्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग)-सह-चुनाव न्यायाधिकरण,(संक्षेप में, 'चुनाव न्यायाधिकरण') दानापुर, जिला पटना, बिहार द्वारा निर्वाचन मामला सं. 08/2016 में दिनांक 11.10.2018 और 11.4.2019 में पारित आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है। नतीजतन, नौबतपुर प्रखंड के अंतर्गत आरतीपुर ग्राम पंचायत संख्या 8 के मुखिया पद के लिए उत्तरदाता संख्या 1 के चुनाव को चुनौती देने वाले अपीलार्थी द्वारा दायर उपरोक्त संख्या वाले चुनाव मामले को खारिज कर दिया गया।

3. संक्षेप में कहा गया है कि नौबतपुर प्रखंड के तहत मुखिया, आर्यापुर ग्राम पंचायत संख्या 8 के पद के लिए चुनाव 6.5.2016 पर आयोजित किया गया था, जिसमें अपीलार्थी और उत्तरदाता संख्या 1 ने 11 अन्य लोगों के साथ उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और 4.6.2016 पर वोटों की गिनती के बाद, उत्तरदाता संख्या 1 को निर्वाचित घोषित किया गया था। हालाँकि, गिनती के दौरान, अपीलार्थी ने देखा था कि उसके पक्ष में

डाले गए वैध मतों की संख्या को अस्वीकार किया जा रहा था, जबकि उत्तरदाता संख्या 1 के पक्ष में अमान्य मतों को भी स्वीकार और गिना जा रहा था। उत्तरदाता नंबर 1 को 154 मतों के अंतर से निर्वाचित घोषित किया गया था। इस पृष्ठभूमि में, अपीलार्थी ने चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष एक चुनाव मामला दायर किया, जिसमें उत्तरदाताओं सं. 1 और उसे (अपीलार्थी) निर्वाचित घोषित करना। अपीलार्थी ने विशेष रूप से गणना प्रक्रिया के दौरान की गई अनियमितताओं के बारे में आरोप लगाया, जिसमें यह भी शामिल था कि स्वस्तिक प्रतीक दबी हुई हल्की स्याही को अपीलार्थी के पक्ष में नहीं गिना जा रहा था और उस ओर से शिकायत किए जाने के बावजूद, निर्वाचन अधिकारी द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया था। साथ ही, यह भी देखा गया कि उत्तरदाता संख्या 1 के पक्ष में डाले गए कुछ अमान्य मतों को स्वीकार कर लिया गया और उस ओर से की गई आपत्ति की अवहेलना करते हुए वैध के रूप में गिना गया। चुनाव मामला सुनवाई के लिए आगे बढ़ा और संबंधित पक्षों द्वारा पेश किए गए गवाहों के साक्ष्य को दर्ज करने के बाद, चुनाव न्यायाधिकरण ने साक्ष्य के उचित मूल्यांकन के बाद, अपीलार्थी की शिकायत को स्वीकार कर लिया कि चुनाव अधिकारी द्वारा तैयार किया गया परिणाम पत्रक उचित नहीं था क्योंकि वोटों की गिनती अधिकारियों द्वारा नियमों के अनुसार नहीं की गई थी। चुनाव न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी के पक्ष में तथ्य के निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए आगे बढ़े और निम्नलिखित शब्दों में इस मुद्दे का उत्तर दिया:-

"

दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ-साथ अभिलेख पर वाद से यह प्रतीत होता है कि आवेदक ने अपनी शिकायत में सभी भौतिक तथ्यों को लाने के लिए अपने स्तर पर पूरी कोशिश की है और अपने साक्ष्यों द्वारा समर्थित है, यह भी प्रतीत होता है कि जैसे ही वादी को पता चला कि वोटों की गिनती करते समय कुछ अनियमितताएं हो रही हैं और उसे

पता चला कि उसके 216 वैध वोटों को मतपत्र पर हल्की स्याही के कारण खारिज कर दिया गया है, लेकिन उसी प्रकार की गिनती वापस आए उम्मीदवार के पक्ष में की गई है। तुरंत उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फिर से गिनती के लिए एक आवेदन दिया है जिसे प्रदर्श-1 चिह्नित किया गया है, जो उनकी शिकायत में किया गया है और साथ ही मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित है। इस मामले की शिकायत वादी के खारिज किए गए वैध मतों के संबंध में एक प्रथम दृष्टया मामला बनाती है। इस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा उपरोक्त सभी शर्तों को पूरा किया जाता है जिनकी ऊपर चर्चा की गई है। इस प्रकार, इस न्यायाधिकरण के ऊपर की गई चर्चाओं के आलोक में पाया गया कि वर्तमान मामले में मतों की गिनती में अनियमितताएं थीं, तैयार किया गया परिणाम पत्रक अनियमित था, उचित नहीं था और अधिकारियों द्वारा मतों की गिनती नियम के अनुसार नहीं की गई थी। इस प्रकार, यह मुद्दा याचिकाकर्ता के पक्ष में जाता है।”

अंत में, चुनाव न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

“ आदेश

उपरोक्त मुद्दों के आलोक में यह स्पष्ट है कि गिनती में बिहार पंचायत चुनाव नियमों के नियम 79 का गणना अधिकारियों द्वारा पालन नहीं किया गया था और इसलिए इस एकमात्र मुद्दे पर चुनाव याचिका की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन मुद्दा संख्या 3, 4 और 5 में चर्चा के अनुसार इस न्यायाधिकरण ने पाया कि वर्तमान मामले में मतों की गिनती में अनियमितताएं थीं और तैयार किया गया परिणाम पत्रक अनियमित था और उचित नहीं था। तथापि, इस न्यायाधिकरण द्वारा मुद्दा संख्या 6 में यह पाया गया है कि:

(i) विपक्षी सं.1 मुखिया को ठीक से घोषित नहीं किया गया था।

ii) याचिकाकर्ता द्वारा यह साबित नहीं किया गया है कि उसे ओ. पी. नंबर 1

के वोटों से अधिक वोट मिले हैं।

इस प्रकार, ऊपर की गई चर्चा से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को रद्द करने की राहत का अधिकार नहीं है। हालाँकि, उपरोक्त मुद्दों की चर्चाओं और निष्कर्षों से यह भी स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में सक्षम रहा है कि ग्राम पंचायत राज, दरियापुर के मुखिया के पद के लिए अंतिम परिणाम उचित नहीं है और विपक्षी सं. 1 को ठीक से मुखिया के रूप में घोषित नहीं किया गया था, लेकिन अंतिम परिणाम का पता केवल उचित और मिनट की पुनः गिनती से लगाया जा सकता है। इसलिए, याचिकाकर्ता केवल ऊपर चर्चा की गई राहत का हकदार है।

इसलिए, इस मामले में सभी मुद्दों के निष्कर्षों के आलोक में, एतद्वारा आदेश दिया जाता है कि दरियापुर पंचायत, प्रखंड नौबतपुर, जिला पटना के मुखिया पद के लिए अंतिम परिणाम अमान्य घोषित किया जाए। रिटर्निंग उम्मीदवार के रूप में ओ. पी. नंबर 1 के पक्ष में प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित किया जाता है। विपक्षी सं. 15 अर्थात् जिला दंडाधिकारी, पटना सह जिला चुनाव अधिकारी, पटना को आदेश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर मुखिया दरियापुर पंचायत के पद के लिए प्रत्येक बूथ के मतपत्रों की गिनती उनकी देखरेख में करें। जिला दंडाधिकारी, पटना सह चुनाव अधिकारी पटना को यह भी आदेश दिया जाता है कि वे चुनाव सामग्री को अपने हाथ में लें जो पुनः गिनती के उद्देश्य से इस न्यायालय की सुरक्षित हिरासत में रखी गई है और उसके बाद इसे कानून/नियमों के अनुसार रखें। यह भी आदेश दिया जाता है कि पुनर्मतगणना के बाद प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अंतिम परिणाम तैयार किया जाएगा और लौटने वाले उम्मीदवार के पक्ष में प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इस फैसले की एक प्रति जिला दंडाधिकारी सह जिला चुनाव अधिकारी, पटना और चुनाव आयोग को भेजी जाए। इस मामले में लंबित सभी याचिकाओं को दबाए बिना निपटाया जाता है।

तदनुसार, मामले को उन लोगों के खिलाफ लड़ने की अनुमति है जो इस मामले में पेश हुए हैं और पूर्व पक्ष के खिलाफ जो पेश नहीं हुए हैं।

फैसला मेरे द्वारा खुली न्यायालय में सुनाया गया।

मेरे द्वारा टंकण और सही किया गया।”

इस आदेश पर उत्तरदाता सं. 1 उच्च न्यायालय के समक्ष दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले (सी.डब्ल्यू. जे.सी.) सं. 21476/2018 के माध्यम से। विद्वत एकल न्यायाधीश, अभिलेख पर साक्ष्य पर उचित विचार करने के बाद, जैसा कि चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा विचार किया गया था, चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा निम्नलिखित शब्दों में दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष को बरकरार रखते हुए प्रसन्न हुए:-

“.....

इस विषय पर उपरोक्त न्यायिक निर्णयों को ध्यान में रखते हुए जब यह न्यायालय इस बात पर विचार करने के लिए आगे बढ़ता है कि क्या विद्वत चुनाव न्यायाधिकरण ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों पर विचार किया है और क्या ऐसी सामग्रियों के आधार पर मतों की फिर से गिनती के आरोप की सच्चाई के बारे में प्रथम दृष्टया संतुष्टि ली गई है? इस न्यायालय ने पाया कि विद्वत चुनाव न्यायाधिकरण ने चुनाव याचिकाकर्ता के मामले पर चर्चा की है, जिसमें विशेष रूप से कहा गया है कि हल्की स्याही से दबाए गए स्वास्तिक प्रतीक वाले मतपत्रों को चुनाव याचिकाकर्ता के पक्ष में नहीं गिना जा रहा था, जबकि उन्हें वापस आए उम्मीदवार (याचिकाकर्ता) के पक्ष में गिना जा रहा था। चुनाव याचिकाकर्ता के मामले का समर्थन एडब्ल्यू 2, एडब्ल्यू 3, एडब्ल्यू 4 और एडब्ल्यू 5 ने किया था। विद्वान चुनाव न्यायाधिकरण ने उन गवाहों के साक्ष्यों पर चर्चा की है जिन्होंने कहा है कि वे गिनती के समय मौजूद थे और उन्होंने चुनाव याचिकाकर्ता के

मामले का समर्थन किया था। वास्तव में, अखिलेश्वर कुमार नामक एक व्यक्ति, जिसने वि.सा.1 के रूप में गवाही दी है, ने अपने मुख्य परीक्षा में आवेदक के मामले का समर्थन किया है। विद्वत चुनाव न्यायाधिकरण ने विवादित फैसले में उनके साक्ष्य पर भी चर्चा की है। फैसले में चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा की गई चर्चाओं को देखने पर, इस न्यायालय ने पाया कि उसने लौटे उम्मीदवार की ओर से पेश किए गए गवाहों के बयान पर भी विचार किया है। यह पाया गया है कि लौटे उम्मीदवार और उसके गवाहों ने या तो बयान दिया है कि वे गिनती के समय मौजूद नहीं थे या उन्हें वैध या अमान्य मतों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। न्यायाधिकरण ने माना कि लौटे उम्मीदवार ने अपने पक्ष के अन्य गवाहों की तुलना में वैध और अमान्य मतों के बारे में विरोधाभासी बयान दिए हैं। अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण सामग्री के सावधानीपूर्वक अवलोकन के बाद, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि वाद में चुनाव याचिकाकर्ता ने एक स्पष्ट और सकारात्मक आरोप लगाया है और उसने गिनती के समय उपस्थित गवाहों को लाकर अपने आरोपों का समर्थन किया है। इन स्थितियों में यदि चुनाव न्यायाधिकरण ने खुद को प्रथम दृष्टया संतुष्ट पाया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मत की फिर से गिनती की आवश्यकता है, तो इस न्यायालय को कोई अन्य दृष्टिकोण लेने का कोई कारण नहीं मिलता है।

इस न्यायालय की राय में, विद्वत न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित दृष्टिकोण को उचित रूप से लिया है:

“इस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा उपरोक्त सभी शर्तों को पूरा किया जाता है जिनकी ऊपर चर्चा की गई है। इस प्रकार, इस न्यायाधिकरण के ऊपर की गई चर्चाओं के आलोक में पाया गया कि वर्तमान मामले में मतों की गिनती में अनियमितताएं थीं, तैयार किया गया परिणाम पत्रक अनियमित था जो उचित नहीं था और अधिकारी द्वारा मतों की गिनती नियम के अनुसार नहीं की गई थी। अतः यह मुद्दा याचिकाकर्ता के पक्ष में जाता

है।”

उपरोक्त चर्चाओं के आधार पर, इस न्यायालय ने पाया कि मतों की फिर से गिनती के निर्देश को गलत नहीं ठहराया जा सकता है, किसी भी भौतिक अवैधता से कम कोई अवैधता नहीं है और अपने पर्यवेक्षी रिट अधिकार क्षेत्र में बैठे इस न्यायालय को उपरोक्त निर्देश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है।”

हालाँकि, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने मतों की फिर से गिनती से पहले चुनाव को रद्द करने के चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को उलट दिया। इसके बजाय विद्वान एकल न्यायाधीश ने पुनर्मतगणना परिणाम उपलब्ध होने के बाद ही उचित आदेश पारित करने के सीमित उद्देश्य के लिए चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष पक्षों को हटा दिया। वास्तव में, पुनः गणना प्रक्रिया उक्त रिट के लंबित रहने के दौरान पूरी की गई थी और परिणाम को सीलबंद लिफाफे में रखा गया था। नतीजतन, विद्वान एकल न्यायाधीश ने सीलबंद लिफाफे में रखे गए पुनर्मतगणना परिणामों के अवलोकन के बाद परिणामी आदेश पारित करने के लिए चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष पक्षों को खारिज करना उचित समझा।

4. उत्तरदाता सं.1 ने लेटर्स पेटेंट अपील (एलपीए) सं.382/2019 के माध्यम से विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय पर विरोध किया। उक्त अपील के लंबित रहने के दौरान, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्देशों के संदर्भ में, चुनाव न्यायाधिकरण 11.4.2019 पर एक आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ा। चुनाव न्यायाधिकरण ने बिहार चुनाव नियम, 2006 (संक्षेप में, '2006 नियम') के नियम 81 के संदर्भ में, चुनाव परिणाम की घोषणा के लिए सीलबंद लिफाफे में रखी गई रिपोर्ट को जिला चुनाव अधिकारी-सह-जिला दंडाधिकारी, पटना के समक्ष रखने का निर्देश दिया। उत्तरदाताओं नं.1, इसलिए, सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 9655/2019 के माध्यम से चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा पारित

उक्त आदेश दिनांक 11.4.2019 को चुनौती दी। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एलपीए के साथ-साथ रिट याचिका (सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 9655/2019) को एक सामान्य निर्णय द्वारा एक साथ निपटाने के लिए आगे बढ़ाया, जो वर्तमान अपील में चुनौती का विषय है।

5. अपीलार्थी के अनुसार, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने चुनाव न्यायाधिकरण के सुविचारित निर्णय को उलटने में स्पष्ट त्रुटि की, जैसा कि वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति में मतों की पुनः गिनती का निर्देश देने की आवश्यकता के संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सही ठहराया गया था। खंड पीठ ने मतों की फिर से गिनती के संबंध में निर्देश को दरकिनार करने से पहले चुनाव न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विश्लेषण किए गए मामले के तथ्यात्मक पहलुओं से निपटने की भी जहमत नहीं उठाई। **भाभी बनाम शिव गोविंद और अन्य¹ तथा महेंद्र प्रताप बनाम कृष्ण पाल और अन्य²** में इस न्यायालय की निर्णय का केवल उल्लेख किया गया है। वास्तव में, खंड पीठ ने कोई जांच नहीं की, दलीलों और सबूतों का बहुत कम विश्लेषण किया, लेकिन यह पाया कि चुनाव न्यायाधिकरण ने मतपत्रों का निरीक्षण किए बिना या इस पर प्रथम दृष्टया राय बनाए बिना अपीलार्थी/चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री के आधार पर, मतों की पुनः गिनती के निर्देश में त्रुटि हुई। विवादित निर्णय खंड पीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश को अपने प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण को दर्ज करते हुए पुनः प्रस्तुत करता है और चुनाव न्यायाधिकरण के सुविचारित निर्णय को उलटने के लिए उसमें व्यक्त विचार को अपनाने के लिए आगे बढ़ता है जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा बरकरार रखा गया था। स्वीकार करते हुए, यह आग्रह किया जाता है कि 24.7.2019 पर पारित अंतरिम आदेश ने अपीलार्थी/चुनाव याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत अभिवचनों और साक्ष्य का विश्लेषण नहीं किया है, जिसने चुनाव न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के विद्वान

1 (1976) 1 एससीसी 687

2 (2003) 1 एससीसी 390

एकल न्यायाधीश की सराहना की थी। उक्त आदेश में केवल इतना उल्लेख किया गया है कि चुनाव न्यायाधिकरण ने इस विषय पर कानून की पूरी अज्ञानता में मतों की फिर से गिनती का आदेश पारित किया, जबकि चुनाव न्यायाधिकरण के साथ-साथ विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिवचनों के साथ-साथ अपीलार्थी/चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का विधिवत विश्लेषण किया था ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अपीलार्थी/चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा किए गए मामले को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत थे कि अधिकारियों ने मतों की गिनती के दौरान गंभीर अनियमितताएं कीं और उस संबंध में लागू नियमों का पालन करने में विफल रहे। अपीलकर्ता यह प्रस्तुत करेगा कि खंडपीठ द्वारा उद्धृत किए गए निर्णय किसी भी प्रकार से सहायक नहीं हैं और वर्तमान मामले के विशेष तथ्यों में चुनाव न्यायाधिकरण तथा माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए सुविचारित निर्णयों—जिनमें मतों की पुनर्गणना का निर्देश दिया गया है—को पलटने का आधार नहीं बन सकते।

6. उत्तरदाता सं.1 जिसने चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देते हुए एलपीए दायर किया था, तथापि, उसने खंड पीठ के निर्णय का समर्थन किया है और तर्क देगा कि अपीलार्थी/चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा चुनाव याचिका में या उस राहत को प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत किए गए किसी भी साक्ष्य के माध्यम से फिर से गिनती के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया था। विवादित फैसले में संदर्भित इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया जाता है कि न तो चुनाव न्यायाधिकरण और न ही विद्वान एकल न्यायाधीश ने वोटों की फिर से गिनती का निर्देश देने से पहले तय किए गए कानूनी सिद्धांतों पर ध्यान दिया। अपीलार्थी/चुनाव याचिकाकर्ता ने परिणामों की घोषणा से पहले फिर से गिनती के लिए आवेदन नहीं किया और मतपत्रों का निरीक्षण किए बिना, चुनाव न्यायाधिकरण ने मतों की फिर से गिनती का निर्देश दिया, जो अस्वीकार्य था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि विवादित निर्णय में कोई हस्तक्षेप

आवश्यक नहीं है।

7. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अमित पवन और उत्तरदाताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अभय कुमार को सुना है।

8. प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने के बाद, हमें अपीलार्थी के इस तर्क को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि खंडपीठ ने निर्वाचन न्यायाधिकरण के आक्षेपित निर्णय (दिनांक 27.8.2019) को उलट दिया है, जिसे चुनाव मामले के मुकदमे के दौरान अपीलार्थी/चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों और साक्ष्य का विश्लेषण किए बिना विद्वान एकल न्यायाधीश (दिनांक 1) द्वारा उचित रूप से बरकरार रखा गया है। विवादित निर्णय केवल रिट (सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं.9655/2019) और एलपीए के लंबित रहने के दौरान पारित अंतरिम आदेशों का विज्ञापन करता है और यह अवलोकन करता है कि उसमें दर्ज (प्रथम दृष्टया) राय के लिए, मुद्दे में मामला अपीलार्थी/चुनाव याचिकाकर्ता के खिलाफ और उत्तरदाता सं. 1 के पक्ष में जवाब देने का हकदार है। यह अपील के तहत निर्णय के निम्नलिखित उद्धरण से स्पष्ट है:-

“ ”

ऊपर निकाले गए आदेशों के अवलोकन से, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाने वाला विवादास्पद प्रश्न यह है कि क्या न्यायाधिकरण ने लगाए गए आरोपों पर मतों की फिर से गिनती का आदेश देने के लिए कानून के अनुसार कार्रवाई की थी। दोहराए बिना तथ्यों और यहां तक कि 24 जुलाई, 2019 के हमारे आदेश में निकाली गई कानून की स्थिति में, हम पाते हैं कि उत्तरदाता चुनाव-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता हमें ऊपर उद्धृत अंतरिम आदेश में हमारे द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण लेने के लिए सफलतापूर्वक मना नहीं सके। (1976) 1 एससीसी 687 में प्रतिवेदित भाभी बनाम शीओ गोबिंद और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को

ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि विवादित निर्णय में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा बरकरार रखे गए पुनर्मूल्यांकन का आदेश, इसलिए, अस्थिर है क्योंकि यह कानून के अनुरूप नहीं है। न्यायाधिकरण ने मतपत्रों का निरीक्षण किए बिना या ऐसी सामग्री के आधार पर प्रथम दृष्टया राय बनाए बिना, जिसमें जाना आवश्यक था, फिर से गिनती का आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ा, जिसे कानून में कायम नहीं रखा जा सकता है। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश इसे बरकरार नहीं रख सकते थे।

उपरोक्त तथ्यों के विवरण से यह प्रतीत होता है कि 6 मार्च, 2019 के निर्णय के बाद भी न्यायाधिकरण ने काफी जल्दबाजी में काम किया है और हमारी राय में, 11 अप्रैल, 1999 को आदेश पारित करने की कार्यवाही में कोई भी कार्रवाई एक अतिक्रमण की प्रकृति में थी ताकि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को वस्तुतः दरकिनार किया जा सके। इस तथ्य पर विद्वान एकल न्यायाधीश ने 18 जून, 2019 के अंतरिम आदेश को पारित करते हुए ध्यान दिया है, जो 2019 के सीडब्लूजेसी सं.9655 में ऊपर निकाला गया है, जिसके साथ हम पूरी तरह से सहमत हैं।

इसलिए न्यायाधिकरण ने न केवल एक त्रुटि की, बल्कि न्यायाधिकरण की कार्रवाई को स्पष्ट रूप से कानून में द्वेष के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसलिए न्यायाधिकरण को 6 मार्च, 2019 के फैसले में की गई टिप्पणियों का पालन किए बिना भी परिणाम घोषित करने के लिए कोई निर्देश जारी करने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। इसलिए, न्यायाधिकरण द्वारा मामले से निपटने के इस तरीके की, विशेष रूप से, मामले की पृष्ठभूमि में, उन दलीलों के आलोक में सराहना नहीं की जा सकती है जो एक न्यायाधिकरण द्वारा फिर से गिनती का आदेश देने से पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में कानूनी मुद्दे पर आगे बढ़ाई गई हैं।

हालाँकि, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मंगलम ने इस बात पर जोर

दिया कि यदि अपील स्वीकार कर ली जाती है और 11 अप्रैल, 2019 का आदेश रद्द कर दिया जाता है, तब भी मामले को स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। उनका तर्क यह है कि अभिलेख में मौजूद दलीलों की प्रकृति को देखते हुए, चुनाव याचिका स्वयं विचारणीय नहीं है, जो पुनर्मतगणना या चुनाव याचिका में लगाए गए आरोपों की सुनवाई के लिए कोई मामला नहीं बनाती। न्यायाधिकरण द्वारा मुद्दा संख्या 1 तैयार करने और प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर दिए गए उत्तर की ओर इशारा करते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव याचिका इस आधार पर विचारणीय पाई गई है कि पुनर्मतगणना का मामला बनता है। उन्होंने दलील दी कि यह एक विपरीत प्रक्रिया थी, जिसमें निष्कर्ष दर्ज किया जाता है, क्योंकि एक बार जब अभिलेख पर इस आशय का सबूत मौजूद था कि पुनर्गणना के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था, जो कि रिटर्निंग अधिकारी के बयान से स्पष्ट है, तो उस स्थिति में मुद्दा संख्या 1 पर गलत निर्णय लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि स्ट्रांग रूम से अभिलेखों को चुनाव याचिकाकर्ता के पुत्रों की निजी अभिरक्षा में न्यायालय में स्थानांतरित करने से संबंधित घटना भी एक अतिरिक्त आधार थी, इस तथ्य के अलावा कि न्यायालय ने स्वयं सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए एक विविध आवेदन पर विचार किया था। उनका तर्क है कि जानबूझकर की गई झूठी दलील के कारण चुनाव याचिकाकर्ता को चुनाव याचिका जारी रखने के अधिकार से स्पष्ट रूप से वंचित कर दिया और जिसके लिए विद्वान अधिवक्ता ने महेंद्र प्रताप बनाम कृष्ण पाल एवं अन्य (2003) 1 एससीसी 390 के मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा किया है।

अतः संक्षेप में तर्क यह है कि इस न्यायालय को स्वयं यह अभिनिर्धारित करना चाहिए कि चुनाव याचिका विचारणीय नहीं थी और परिणामस्वरूप, मामले को संबंधित न्यायाधिकरण को वापस भेजने का कोई अवसर नहीं है।

उपरोक्त प्रस्तुतियों का जवाब देते हुए, चुनाव याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. के. शाही ने प्रस्तुत किया कि यह मानते हुए भी कि न्यायाधिकरण ने उचित निष्कर्षों को दर्ज किए बिना फिर से गिनती का आदेश देने के लिए आगे बढ़ने में त्रुटि की है, भले ही इसे स्वीकार नहीं किया गया हो, फिर भी मामले को न्यायाधिकरण में वापस जाना होगा, क्योंकि रखरखाव का मुद्दा मुख्य मुद्दा नहीं था, और यह फिर से गिनती का मुद्दा था जिसने पूरे मुकदमे का आधार बनाया। यह निर्धारित करने के लिए कि प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर फिर से गिनती की अनुमति होगी या नहीं, यह स्वयं न्यायाधिकरण द्वारा जांच का विषय होगा न कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में इस न्यायालय द्वारा। इसलिए, वह प्रस्तुत करता है कि मामले को अभिलेख पर साक्ष्य और उन अभिवचनों को ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिए जो इंगित करते हैं कि लगाए गए आरोपों पर फिर से गिनती करने का प्रयास करने के लिए पर्याप्त सामग्री थी।

बिहार राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने भी अपनी दलीलें आगे बढ़ाते हुए तर्क दिया है कि भाभी बनाम शीओ गोबिंद और अन्य (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पालन किया जाना चाहिए।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और अभिलेखों को पढ़ने के बाद और यहाँ ऊपर हमारे द्वारा जो दर्ज किया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि पुनः गिनती के आदेश को बनाए नहीं रखा जा सकता है क्योंकि न्यायाधिकरण ने जल्दबाजी में काम किया और न्यायाधिकरण की कार्रवाई बाद में 11 अप्रैल, 2019 का आदेश पारित करने में भी स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि यह एक ऐसा आदेश नहीं है जिसे या तो कानून में बनाए रखा जा सकता है या जैसा कि भाभी बनाम शीओ गोबिंद और अन्य (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप बताया जा सकता

है।

अतः पीठासीन अधिकारी द्वारा जिस तरीके से कार्यवाही का संचालन किया गया है, उसकी सराहना नहीं की जा सकती है। इस पृष्ठभूमि में और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन करने के बाद, हम पाते हैं कि मामले के प्रेषित होने पर, विवादित आदेश पारित करने वाले उक्त पीठासीन अधिकारी को वर्तमान विवाद का निर्णय करने के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए।

तदनुसार, वर्तमान अपील (2019 की एल.पी.ए. सं.382) की अनुमति है। विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 6 मार्च, 2019 के विवादित फैसले को रद्द कर दिया गया है।

न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 11.10.2018 पर पारित पुनर्मतगणना के आदेश को भी रद्द कर दिया गया है। इसलिए न्यायाधिकरण द्वारा 11 अप्रैल, 2019 को पारित आदेश को भी कायम नहीं रखा जा सकता है और तदनुसार इसे दरकिनार कर दिया जाता है। 2019 का सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं.9655 भी तदनुसार अनुमत है।

यह मामला अब न्यायाधिकरण को भेजा जाएगा, जिसमें पटना के विद्वान जिला न्यायाधीश को निर्देश दिया जाएगा कि उक्त चुनाव याचिका को उस अधिकारी के अलावा चुनाव याचिका पर मुकदमा चलाने के लिए सशक्त रैंक के एक अधिकारी को नामित किया जाए, जिसने पहले इस मामले को निपटाया था।

उपरोक्त निर्देशों के साथ, अपील (2019 का एल.पी.ए. सं.382) और 2019 की रिट याचिका (सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं.9655) को तदनुसार अनुमति दी जाती है।”

(जोर दिया गया)

यह मानते हुए कि हमें दिनांक 1 और 2 के विस्तृत अंतरिम आदेशों का

संज्ञान लेना था, यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि कार्यवाही के उस स्तर पर भी, खंड पीठ को चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों और साक्ष्य का विश्लेषण करने का अवसर मिला है जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश को अनुशंसित किया गया है। निर्वाचन न्यायाधिकरण द्वारा इस प्रकार अभिलिखित तथ्यों के निष्कर्ष को उलट दिए बिना, केवल **भाभी (उपरोक्त) और महेंद्र प्रताप (उपरोक्त)** में इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख किए बिना, खंडपीठ वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों में निर्वाचन न्यायाधिकरण द्वारा निर्देशित पुनर्मतगणना के आदेश को बाधित नहीं कर सकती थी। चूंकि, अपीलार्थी/चुनाव याचिकाकर्ता ने न केवल उत्तरदाताओं संख्या 1 के पक्ष में डाले गए वैध मतों और अमान्य मतों की गिनती के दौरान अधिकारियों द्वारा की गई गंभीर अनियमितताओं के बारे में अनुरोध किया था, बल्कि उस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए गवाहों से भी पूछताछ की थी, जैसा कि चुनाव न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने उल्लेख किया था।

9. वास्तव में, भाभी (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने मतों के निरीक्षण या पुनः गिनती के निर्देश जारी करने के लिए रूपरेखा को निम्नलिखित शब्दों में चित्रित किया है:-

“15. इस प्रकार समय-समय पर इस न्यायालय के विभिन्न प्राधिकरणों के बारीकी से और सावधानीपूर्वक विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय द्वारा मतपत्रों का निरीक्षण या उस मामले के लिए नमूना निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं:

(1) कि मतपत्र की गोपनीयता बनाए रखना महत्वपूर्ण है जो पवित्र है और तुच्छ, अस्पष्ट और अनिश्चितकालीन आरोपों पर इसका उल्लंघन नहीं होने दिया जाना चाहिए;

(2) कि निरीक्षण की अनुमति देने से पहले, निर्वाचित उम्मीदवार के खिलाफ लगाए गए आरोप स्पष्ट और विशिष्ट होने चाहिए और भौतिक तथ्यों के पर्याप्त बयानों द्वारा समर्थित होने चाहिए;

(3) न्यायालय को पुनर्मतगणना के लिए लगाए गए आरोपों की सच्चाई के संबंध में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर प्रथम दृष्टया संतुष्ट होना चाहिए;

(4) कि न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि निरीक्षण के लिए अनुरोध करने के लिए पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करना आवश्यक और अनिवार्य है;

(5) कि न्यायालय को दिए गए विवेकाधिकार का उपयोग इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए ताकि आवेदक चुनाव को अमान्य घोषित करने के लिए मछली सामग्री की दृष्टि से घूमती हुई जांच में शामिल हो सके; और

(6) कि दिए गए मामले के विशेष तथ्यों पर नमूना निरीक्षण का आदेश दिया जा सकता है कि न्यायालय को पुनः गिनती के लिए लगाए गए आरोपों की सच्चाई के बारे में प्रथम दृष्टया संतुष्टि के लिए और आश्वासन दिया जाए, न कि सामग्री को बाहर निकालने के उद्देश्य से।”

यदि ये सभी परिस्थितियाँ न्यायाधीश के दिमाग में आती हैं और वह संतुष्ट होता है कि इन शर्तों को किसी दिए गए मामले में पूरा किया जाता है, तो विवेकाधिकार का प्रयोग निस्संदेह उचित होगा।”

सवाल यह है: क्या मतों की पुनः गिनती के आदेश को उचित ठहराने के लिए भौतिक तथ्यों का स्पष्ट रूप से अनुरोध किया गया है और वर्तमान मामले में अपीलार्थी/चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा यह साबित किया गया है? उस मुद्दे का चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा व्यापक रूप से विश्लेषण किया गया है, जैसा कि इसके द्वारा किया गया

विक्षेपण से स्पष्ट है, जिसकी विद्वान एकल न्यायाधीश ने सराहना की। चूँकि अपीलार्थी ने चुनाव याचिका में लगाए गए आरोप की पुष्टि की थी और चुनाव न्यायाधिकरण ने उक्त दावे के बारे में आश्वस्त होने के बाद फिर से गिनती का आदेश जारी किया। चुनाव न्यायाधिकरण के उस दृष्टिकोण में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है और न ही यह सुझाव देना संभव है कि चुनाव न्यायाधिकरण या विद्वान एकल न्यायाधीश गिनती के दौरान अधिकारियों द्वारा की गई गंभीर अनियमितताओं के बारे में आरोप को साबित करने की आवश्यकता के बारे में सचेत नहीं थे।

10. इसी तरह, **महेंद्र प्रताप (उपरोक्त)** के मामले में, न्यायालय ने उस मामले के तथ्यों में चुनाव याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि दलीलों, हलफनामों या बयानों में गलत बयान न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास था और इससे भी अधिक, उम्मीदवार (चुनाव याचिकाकर्ता) द्वारा परिणाम घोषित होने के बाद निर्वाचन अधिकारी को फिर से गिनती का आवेदन दिया गया था, जिस पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जा सकता था। **सोहन लाल बनाम बाबू गांधी और अन्य³** के मामले में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने राय दी है कि यह तथ्य कि गिनती के दौरान उम्मीदवार द्वारा फिर से गिनती का अनुरोध नहीं किया गया था, चुनाव याचिका दायर करने या चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद चुनाव पर सवाल उठाने वाली चुनाव याचिका में फिर से गिनती का निर्देश देने से नहीं रोकता है। **राम रति (श्रीमती) बनाम सरोज देवी⁴** और अन्य में निर्णय, खारिज कर दिया गया और इसके बजाय न्यायालय ने कहा कि एक चुनाव याचिका में, परिणाम की घोषणा के बाद, न्यायालय या न्यायाधिकरण वोटों की फिर से गिनती का निर्देश दे सकता है, भले ही पार्टी ने निर्वाचन अधिकारी को वोटों की फिर से गिनती के लिए लिखित रूप में आवेदन नहीं

3 (2003) 1 एससीसी 108

4 (1997) 6 एससीसी 66

किया हो। अधिनियम या नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो न्यायालय या न्यायाधिकरण को मतों की पुनः गिनती का निर्देश देने से रोकता हो। न्यायालय ने कंडिका ग्राफ 14 में इस प्रकार टिप्पणी की:-

“14. धारा 122 और नियमों को देखते हुए, हम राम रति मामले (1997) 6 एस. सी. सी. 66 में निर्धारित अनुपात से सहमत नहीं हैं। यह कहना सही नहीं है कि चुनाव याचिका में, परिणाम की घोषणा के बाद, न्यायालय या न्यायाधिकरण वोटों की फिर से गिनती का निर्देश नहीं दे सकता है जब तक कि पार्टी ने पहले वोटों की फिर से गिनती के लिए लिखित रूप में आवेदन नहीं किया हो। अधिनियम में या नियमों के तहत कोई निषेध नहीं है जो न्यायालय या न्यायाधिकरण को वोटों की फिर से गिनती का निर्देश देने से रोकता है। अन्यथा, हो सकता है कि किसी पक्ष को पता न हो कि परिणाम घोषित होने तक फिर से गिनती आवश्यक है। इस चरण में यह उसके लिए निर्वाचन अधिकारी को पुनः गणना के लिए आवेदन करना संभव नहीं होगा। उनका एकमात्र उपाय धारा 122 के तहत चुनाव याचिका दायर करना होगा। ऐसे मामले में, न्यायालय या न्यायाधिकरण याचिका पर विचार करने के लिए बाध्य है और जहां कोई मामला बनाया जाता है, वह पक्षों के नेतृत्व में साक्ष्य के आधार पर फिर से गिनती का निर्देश दे सकता है। वर्तमान मामले में, परिणाम घोषित करने में स्पष्ट त्रुटि थी। इसलिए हमारा मानना है कि राम रति मामले (1997) 6 एस. सी. सी. 66 में निर्धारित अनुपात सही नहीं है।”

11. एक प्राथमिकता के रूप में, हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि खंड पीठ ने चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा पारित सुविचारित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप किया है, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उचित रूप से बरकरार रखा गया था, जिसमें मतों की फिर से गिनती का निर्देश दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि पुनःगणतरी के बाद, अपीलार्थी/चुनाव याचिकाकर्ता ने 95 अतिरिक्त वैध मत प्राप्त किए हैं,

जो उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा प्राप्त वैध मतों से अधिक हैं। इसने अपीलार्थी द्वारा स्थापित चुनौती को और मजबूत किया है कि अधिकारियों ने अपीलार्थी द्वारा प्राप्त वैध मतों में जानबूझकर हेरफेर करने के लिए गंभीर अनियमितताएं की थीं। नतीजतन, हमें मतों की फिर से गिनती के आदेश को बरकरार रखने में कोई संकोच नहीं है, जैसा कि चुनाव न्यायाधिकरण (दिनांक 11.10.2018) द्वारा पारित किया गया है और विद्वान एकल न्यायाधीश (दिनांक 6.3.2019 के आदेश के अनुसार) द्वारा वर्तमान मामले के तथ्यों में उचित रूप से बरकरार रखा गया है।

12. अगला सवाल चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्देश की शुद्धता के बारे में है, जिसमें परिणाम की घोषणा के लिए जिला चुनाव अधिकारी-सह-जिला दंडाधिकारी, पटना के समक्ष सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट रखने का आदेश दिया गया है। यह निर्देश भले ही अनुचित हो, लेकिन मतों की फिर से गिनती के क्रम को प्रभावित नहीं करेगा। यह उच्च न्यायालय के लिए खुला था कि वह चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा जारी निर्देश को ढाले और इसके बजाय बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 140 के तहत घोषणा जारी करे, जो इस प्रकार है:-

“140. जिन आधारों पर लौटे उम्मीदवार के अलावा किसी अन्य उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जा सकता है-(1) यदि कोई व्यक्ति ने चुनाव याचिका दायर की है, उसने लौटने वाले उम्मीदवार के चुनाव पर सवाल उठाने के अलावा, एक घोषणा का दावा किया है कि वह स्वयं या कोई अन्य उम्मीदवार विधिवत निर्वाचित हुआ है और निर्धारित प्राधिकरण की राय है -

(क) कि वास्तव में याचिकाकर्ता या ऐसे अन्य उम्मीदवार को वैध मतों का बहुमत प्राप्त हुआ; या

(ख) लेकिन भ्रष्ट प्रथाओं से लौटे उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों के लिए

याचिकाकर्ता या ऐसे अन्य उम्मीदवार ने वैध मतों का बहुमत प्राप्त किया होगा, निर्धारित प्राधिकरण लौटे उम्मीदवार के चुनाव को अमान्य घोषित करने के बाद याचिकाकर्ता या ऐसे अन्य उम्मीदवार को विधिवत निर्वाचित घोषित करेगा।

(2) निर्धारित प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।”

दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को निर्वाचन न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 1 के कार्यकारी आदेश को इस प्रभाव से ढालना या संशोधित करना चाहिए था कि वापस लौटे उम्मीदवार (उत्तरदाता संख्या 1) का चुनाव अमान्य हो और रद्द कर दिया जाए और अपीलार्थी (चुनाव याचिकाकर्ता) को फिर से गिनती के बाद अधिक वैध वोट प्राप्त करने के बाद विधिवत निर्वाचित घोषित किया जाए। परिणामस्वरूप, इस अपील में, हम उस घोषणा को जारी करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

13. चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश, दिनांक आई.डी. 1, जो सी. डब्ल्यू.जे.सी. सं. आई. डी. 2 का विषय था, ने भी न्यायाधिकरण के अभिलेख/दस्तावेजों की जालसाजी का आरोप लगाते हुए उसके समक्ष दायर आवेदन पर विचार किया। न्यायाधिकरण ने ठीक ही कहा है कि यह एक अलग मामला है और इसके लिए स्वतंत्र जांच की आवश्यकता होगी, जिसके लिए याचिका को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत एक याचिका के रूप में माना गया है, जिससे कानून के अनुसार निपटा जा सके। जहां तक चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा दिनांकित 11.4.2019 आदेश के माध्यम से जारी किए गए उस निर्देश का संबंध है, वही इस अपील का विषय नहीं है। दूसरे शब्दों में, हमने केवल बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 140 के संदर्भ में मतों की फिर से गिनती और उचित घोषणा जारी करने के संबंध में चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्दिष्ट निर्देश से उत्पन्न मुद्दों पर विचार किया है। उत्तरदाता संख्या 1 ने निर्णय के लिए मामला सुरक्षित रखे जाने के बाद दायर लिखित प्रस्तुतियों के माध्यम से कुछ

तथ्यात्मक मामलों की ओर रुख किया है, ताकि मतों की पुनः गिनती के परिणाम पर सवाल उठाया जा सके। संभवतः, कमीशन या चूक के कथित कार्य पहले से ही दं.प्र.सं. की धारा 340 के तहत शुरू की गई कार्यवाही का विषय हैं। यह हमें इस मामले का निपटारा करने से रोकने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह ध्यान दिया गया है कि उत्तरदाता संख्या 1 खंड पीठ के समक्ष उन आधारों पर सफल हुआ था जिन्हें हम पहले ही स्वीकार कर चुके हैं और खारिज कर चुके हैं। विवादित फैसले में नए तथ्यात्मक मामलों का उल्लेख नहीं मिलता है। उत्तरदाताओं संख्या 1 के लिए यह खुला रहेगा कि वह दं.प्र.सं. की धारा 340 के तहत कार्यवाही को आगे बढ़ा सके, जिसका निर्णय कानून के अनुसार अपने गुण-दोष के आधार पर करना होगा।

14. तदनुसार, यह अपील सफल होती है। विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। इसके बजाय, चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दायर निर्वाचन आयोग सं. 08/2016 के चुनाव मामले की अनुमति दी जाती है। अधिनियम की धारा 140 के तहत एक घोषणा जारी की जाती है कि उत्तरदाताओं संख्या 1 का वापस लौटे उम्मीदवार के रूप में चुनाव अमान्य है, और इसके बजाय हम अपीलार्थी/चुनाव याचिकाकर्ता को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में सबसे अधिक वोट और विषय चुनाव में उत्तरदाताओं संख्या 1 की तुलना में 95 अधिक वैध वोट प्राप्त करके विधिवत निर्वाचित घोषित करते हैं।

15. अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होता है। लंबित अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

अपील का निपटारा किया गया।

कल्पना के. त्रिपाठी

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।